आतंकवाद पर भारत का दो टूक संदेश

- भारत ने फिर दोहराई जीरो टॉलरेंस नीति
- ऑपरेशन सिंदूर को ठहराया पूरी तरह सही
- चीन की बीआरआई नीति पर हमला

बीजिंग,16 जुलाई.चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) की बैठक में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन दोनों को कड़ा संदेश दिया है.

विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी रखेगा. भारत के इस कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सुर नरम पड़ते दिखे.विदेश मंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगा. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के जवाब में की गई कार्यवाही के तौर पर बिल्कुल सही ठहराया. उन्होंने जोर देकर कहा कि एस.सी.ओ. समूह को आतंकवाद और चरमपंथ से निपटने के अपने मूल उद्देश्य पर कायम रहना चाहिए और इस चुनौती से निपटने में कोई समझौता नहीं करना चाहिए.पहलगाम हमला जम्मू-कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने की साजिश के तहत किया गया था. भारत ने स्पष्ट किया कि वह आतंकवाद का सामना करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया में दृढ़ रहेगा.

एस.सी.ओ. विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री ने कहा कि भारत नए विचारों और प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाएगा

> भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को सहयोग दिए जाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों में चीन द्वारा बाधा डाले जाने के मामलों को लेकर चिंता के बीच, विदेश मंत्री ने एस.सी.ओ. से आतंकवाद से निपटने में कोई समझौता नहीं करने वाला रुख अपनाने का आह्वान किया.विदेश मंत्री ने संघर्ष, प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आर्थिक अस्थिरता पर भी चिंता जताई और दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया.

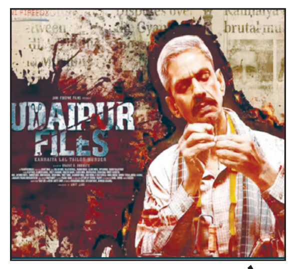

'उदयपुर फाइल्स' के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नयी दिल्ली, 16 जुलाई. उच्चतम न्यायालय ने उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर बनी हिंदी फिल्म %उदयपुर फाइल्स% पर लगी अदालती रोक हटाने से बुधवार को इनकार कर दिया.न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम रोक संबंधी आदेश में फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार निर्देशानुसार फिल्म की जांच कर सकती है.

रूस ने अमेरिका की शर्तें ठुकराईं

युद्धविराम पर राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी को रूस ने नकारा

मॉस्को/कीव, 16 जुलाई.रूस ने यूक्रेन युद्धविराम पर सहमति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 50 दिनों के अल्टीमेटम को खारिज करते हुए अमेरिका की कड़े टैरिफ लगाए जाने की धमकी को अस्वीकार्य करार दिया.

रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने मंगलवार को ज़ोर देकर कहा कि उनका देश यूक्रेन संघर्ष के कूटनीतिक समाधान का पक्षधर है और बातचीत के लिए तैयार है.उन्होंने कहा यदि इसका उचित जवाब नहीं मिलता है और राजनयिक स्तर पर इससे कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता है तो हमारा विशेष सैन्य अभियान जारी रहेगा.उन्होंने कहा कि रूस अपनी बात पर अडिग है और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) इसे गंभीरता से लेंगे. ट्रंप ने मंगलवार को उन आरोपों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने यूक्रेन को रूसी क्षेत्रों में घुसकर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया था.

रूसी विदेश मंत्रालय ने की हथियारों की आपूर्ति की निंदा

उन्होंने कहा कि वह इस संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन को केवल यह सलाह दी कि उसे लंबी दूरी के हथियारों से रूस को निशाना नहीं बनाना चाहिए .इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय ने हथियारों की आपूर्ति की निंदा करते हुए कहा कि यह इस बात का सबूत है कि नाटो देश शांति में रुचि नहीं रखते. उधर यूक्रेन की संसद ने मंगलवार को देश की युद्धकालीन स्थिति और सैन्य लामबंदी को पांच नवंबर यानि 90 दिनों तक बढ़ाने के लिए मतदान किया.

संसद संचालन सरकार की जिम्मेदारी

कांग्रेस प्रभारी जयराम ने कहा विपक्ष से सहमति जरूरी है

नयी दिल्ली, 16 जुलाई.संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस ने सरकार को कहा है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए उसका विपक्ष के साथ सहमति बनाकर चलना आवश्यक है.

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार का दायित्व संसद का शांतिपूर्वक संचालन करना है और संसद चले इसके लिए सरकार को विपक्ष के साथ सहमति बनाकर चलना होगा. उनका कहना था कि प्राय: देखा गया है कि इस सरकार ने पहले ऐसा नहीं किया है और दूसरे दलों को महत्व नहीं दिया है और सरकार अचानक विधेयक लाकर उसे संसद में बिना चर्चा के पारित करा देती है.उन्होंने कहा, जब सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति होगी, तभी संसद ठीक से चलेगी और यह आम सहमति बनाने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है. ऐसा हर सरकार में होता आया है और हमने कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ये होते देखा है, लेकिन दुर्भाग्य से, पिछले 11 वर्षों में जिस तरह से संसद में अचानक विधेयक पेश किए जाते हैं.

दिल्ली में बनेगा हरित ई-वेस्ट पार्क : सिरसा

नयी दिल्ली, 16 जुलाई. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में देश के पहले सौ प्रतिशत ग्रीन ई-वेस्ट इको पार्क के लिए नॉर्वे और हांगकांग के सफल मॉडल पर अध्ययन करायी जा रही है.सिरसा ने बुधवार को कहा, सिर्फ ढांचा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में लोगों और सरकारों का विश्वास बढ़े. इसके लिए हम दुनिया भर के सफल मॉडलों का अध्ययन कर रहे हैं, खासकर नॉर्वे और हांगकांग में, जहां ई-वेस्ट प्लांट शहरों के बीच होते हुए भी शून्य प्रदूषण फैलाते हैं.

जम्मू-कश्मीर को बनाओ राज्य

- खरगे और राहुल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
- लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करो
- जनता के अधिकारों की हो रक्षा

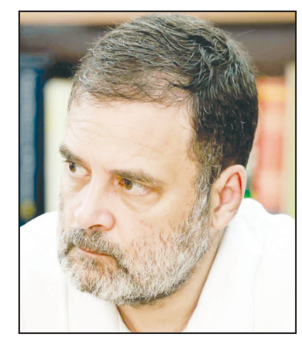

नयी दिल्ली, 16 जुलाई.कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू -कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए विधेयक लाने की मांग की है.

> उन्होंने कहा कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने से वहां की जनता की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी और इससे वहां के लोगों के अधिकार, भूमि और पहचान की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.जम्मू -कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि पहले किसी भी सरकार ने किसी भी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में नहीं बदला है.

हज़ारों अफगान नागरिक तालिबान के डर से भागे ब्रिटेन

लंदन, 16 जुलाई. अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद लोगों की व्यक्तिगत जानकारी लीक होने पर हज़ारों नागरिक एक गुप्त योजना के तहत ब्रिटेन आ गए हैं.रिपोर्ट के अनुसार अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन जाने के लिए आवेदन करने वाले लगभग 19,000 लोगों की व्यक्तिगत जानकारी फरवरी 2022 में लीक हो गई थी.

करुणा विश्वविद्यालय का भव्य दीक्षांत

आइजोल,15 जुलाई. पश्चिमी घाट की शांत तलहटी में स्थित करुणा प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ने अपना 31वां दीक्षांत समारोह बड़े ही भव्यता और शैक्षणिक गौरव के साथ मनाया. इस समारोह में मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री लालदुहोमा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्हें उनकी अनुकरणीय जन सेवा और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए डॉक्टर ऑफ लेटर्स (मानद उपाधि) की उपाधि से सम्मानित किया गया. अपने दीक्षांत भाषण में,लालदुहोमा ने करुणा की आस्था-संचालित शिक्षा और तकनीकी प्रगति के एक आदर्श के रूप में प्रशंसा की और स्नातकों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं.

दिल्ली को जंगलराज बना दिया : केजरीवाल

नई दिल्ली,16 जुलाई. के पांच निजी स्कूलों को बुधवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से एक बार फिर दहशत फैल गई. इन स्कूलों को तुरंत खाली कराना पड़ा.

यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली के स्कूलों को ईमेल के जरिए बम रखे होने की धमकी मिली है. पिछले दो दिनों में मिली धमकियां जांच में झूठी साबित हुई हैं.लगातार मिल रही इन धमकियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर तीखा प्रहार किया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में जंगलराज बनाने पर तुली है.

उन्होंने एक दिन पहले भी धमकियों को लेकर बीजेपी की चार इंजन वाली सरकारों को विफल बताया था.

आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं. पार्टी ने एक्स पर कहा, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है लेकिन बीजेपी की पुलिस और जांच एजेंसियां अभी तक एक सुराग तक नहीं ढूंढ़ सकी हैं. पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पुलिस और अपनी सभी जांच एजेंसियों को विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान करने और उन्हें फर्जी केसों में फंसाने में लगा रखा है. उन्होंने चेतावनी दी, अगर गलती से भी किसी दिन एक भी धमकी सच निकली और हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

> केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लगातार तीसरे दिन आज फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली. दिल्ली के लोगों और उनके बच्चों की ना तो गृहमंत्री अमित शाह को कोई चिंता है और ना ही उनकी चार-चार इंजन वाली सरकारों को. दिल्ली को जंगलराज बनाने पर तुली है बीजेपी.

आज का इतिहास

1850 हार्वर्ड वेधशाला ने तारे का पहला फोटोग्राफ लिया.

1919 यूरोपीय देश फिनलैंड में संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई.

1950 पंजाब के पठानकोट शहर के पास भारत की पहली यात्री विमान दुर्घटना.

1987 ईरान और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध टूटे.

1994 धूमकेतू शुमेकर लेवी-9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से टकराया.

1997 भारतीय महिला फ्रीस्टाइल पहलवान पूजा सिहाग का जन्म.

2003 उत्तर पूर्व कांगो के दुनिया शहर में जातीय हिंसा में 54 लोग मारे गये.

खेमका हत्याकांड में पुलिस पर गाज

पटना,16 जुलाई. के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पहली बार पुलिस पर बड़ी गाज गिरी है. लापरवाही बरतने के आरोप में गांधी मैदान थाने के थाना प्रभारी राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है.

पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने थाना प्रभारी के निलंबन की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद की गई है. इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने चार अन्य पुलिसकर्मियों से भी स्पष्टीकरण मांगा है.पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने अपनी समीक्षा के दौरान गांधी मैदान थाने के एसएचओ राजेश कुमार को अपने कर्तव्यों में कई बिंदुओं पर लापरवाह पाया था. इसके बाद उन्होंने कठोर कदम उठाते हुए उनके निलंबन की सिफारिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप एसएचओ राजेश कुमार पर यह कार्रवाई हुई.

आपको बता दें कि गांधी मैदान थाना क्षेत्र के रामगुलाम चौक के पास गोपाल खेमका के आवास के बाहर ही उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. उनका घर गांधी मैदान थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर है. इस हत्याकांड के बाद गोपाल खेमका के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस घटनास्थल पर करीब डेढ़ से दो घंटे की देरी से पहुंची थी. हालांकि, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि इस हत्याकांड की सूचना पुलिस को देर से मिली थी.

लापरवाही पर थाना प्रभारी निलंबित किए गए

जमीन विवाद से जुड़ा हत्या मामला, अशोक साव व उमेश हिरासत में

बंगाली बोलने पर जेल भेजोगे क्या?

भाषाई भेदभाव के खिलाफ ममता का विरोध मार्च

कोलकाता,16 जुलाई.पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ कोलकाता के हृदय में एक विशाल विरोध मार्च निकाला.

बारिश में भीगते हुए, उन्होंने अपनी बंगाली पहचान के मुद्दे को फिर से उठाया.कोलकाता के बीचो-बीच आयोजित इस विरोध मार्च में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता, जिनमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे, मौजूद थे. यह एक एकता का प्रदर्शन था. लगातार बारिश के बीच, लगभग 3 किलोमीटर के रास्ते में बीजेपी, छी छी के नारे गूंजते रहे, जहां तृणमूल की प्रमुख और अन्य नेता चल रहे थे.

लगभग 1,500 पुलिस कर्मियों ने पूरे रास्ते की सुरक्षा की.रैली के बाद, ममता ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र को उन्हें डिटेंशन कैंप में डालने की चुनौती दी. उन्होंने कहा, मैंने तय किया है कि मैं और बंगाली बोलूंगी. मुझे डिटेंशन कैंप में डाल दो. बीजेपी खेला होबे. बस इंतजार करो.

हाईकोर्ट ने की खारिज चुनाव टालने की मांग

नैनीताल, 16 जुलाई. कांवड़ यात्रा के चलते पंचायत चुनाव विलंब से कराने के मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया है और सरकार के ठोस जवाब के बाद याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है.याचिकाकर्ता डा. बैजनाथ की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से इस मामले को चुनौती दी गई थी. मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्याममूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई.पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव और डीजीपी दीपम सेठ की ओर से आज पृथक-पृथक लिखित जवाब दिये गए. दोनों की ओर से कहा गया कि कांवड़ यात्रा पंचायत चुनाव में बाधा नहीं है.

अमेरिका के कई राज्यों में तूफान से तबाही

न्यूयॉर्क,16 जुलाई.संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वोत्तर में आए एक शक्तिशाली तूफान और उसके बाद अचानक आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है.

मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि न्यू जर्सी में बाढ़ के पानी में एक वाहन के बह जाने से दो लोगों की जान चली गई.राज्यपाल फिल मर्फी ने बर्कले हाइट्स में तबाही के बीच खड़े होकर कहा, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है.

तूफान केवल न्यू जर्सी तक ही सीमित नहीं रहा. इसने दक्षिण-मध्य पेंसिल्वेनिया को भी प्रभावित किया, लैंकेस्टर काउंटी की सड़कों पर बाढ़ ला दी.

न्यू जर्सी में बाढ़ से दो लोगों की मौत

न्यूयॉर्क की सड़कों पर जलजमाव

> न्यूयॉर्क के मेयर ने बताया कि शहर की सीवर प्रणाली इतनी अधिक बारिश को संभालने में सक्षम नहीं है. उन्होंने कहा कि नई जल निकासी प्रणाली तैयार करने में समय और बड़ी राशि खर्च होगी, जिस पर काम शुरू हो चुका है.ब्रॉन्क्स नदी का जलस्तर 3.7 फीट तक पहुंच गया, जिसे मध्यम स्तर की बाढ़ माना गया.पेनसिल्वेनिया के लैंकेस्टर काउंटी में 16 जल बचाव अभियान चलाए गए. दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के बीच 7 इंच से अधिक बारिश हुई.

एक नजर में

अमेरिकी रक्षा विभाग ने हटाए 2000 नेशनल गार्ड

लॉस एंजिल्स. अमेरिकी रक्षा विभाग ने लॉस एंजिल्स में तैनात लगभग 4000 कैलिफ़ोर्निया नेशनल गार्ड में से करीब आधे यानी कि 2000 गार्ड को अपने मूल कमान में लौटने का आदेश दिया है.अमेरिका के रक्षा विभाग के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने एक बयान में रक्षा मंत्री पेटे हेगसेथ द्वारा नेशनल गार्ड सदस्यों की तैनाती कम करने के फैसले की घोषणा करते हुए कहा, हमारे सैनिकों के आह्वान पर आगे आने के लिए धन्यवाद, लॉस एंजिल्स में तनाव और अराजकता कम है.बयान में कहा कि संघीय सुरक्षा मिशन ने अपने तात्कालिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं. बयान में यह नहीं बताया गया है कि नेशनल गार्ड के सदस्य कब तक वापस लौटेंगे. जबकि कुछ अधिकारियों ने कहा कि इकाइयां व्यवस्थित तरीके से फिर से तैनात होंगी.

सटीक नकल के लिए नया एआई टूल विकसित

लंदन. ब्रिटेन की एक कंपनी ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 'वॉयस-क्लोनिंग' टूल विकसित किया है जो देश के विभिन्न लहजों को अपने कुछ अमेरिकी और चीनी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अधिक सटीकता से नकल कर सकता है.परंपरागत रूप से एआई उत्पादों को आवाजों के साथ प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अधिकांश डेटा उत्तरी अमेरिकी या दक्षिणी अंग्रेजी भाषी स्रोतों से आता है, जिससे कई कृत्रिम आवाजें एक जैसी लगती हैं.इससे निपटने के लिए ब्रिटीश कंपनी सिंथेसिया ने स्टूडियो में लोगों की रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन सामग्री एकत्र करके, एक साल तक क्षेत्रीय लहजे वाली ब्रिटीश आवाजों का अपना डेटाबेस तैयार किया.

प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में स्कूल रहे बंद

सिरसा. हरियाणा के हिसार के एक निजी स्कूल के प्राचार्य की बीती 10 जुलाई को की गई निर्मम हत्या के विरोध में बुधवार को रोष स्वरूप राज्य के सभी निजी स्कूल बंद रहे.निजी स्कूल संचालकों ने आज जिला मुख्यालयों पर रोष जाहिर करते हुए जिला उपायुक्तों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भजेकर स्कूल सेफ्टी एक्ट को लागू करने के साथ दिवंगत प्राचार्य जगबीर पानू के परिवार को एक करोड़ आर्थिक मदद व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग रखी. इसी तरह सिरसा में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने फेडरेशन ऑफ़ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

मुलाकात भारत-श्रीलंका साझेदारी पर 'पड़ोसी पहले' नीति से ज़ोर

श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने विदेश सचिव से की मुलाकात

नयी दिल्ली,16 जुलाई. श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की.

यह प्रतिनिधिमंडल दो सप्ताह के लिए भारत में रहेगा और इसका उद्देश्य पड़ोसी पहले की नीति को ध्यान में रखते हुए भारत-श्रीलंका साझेदारी को और मज़बूत करना है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के युवा नेताओं के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपने दो सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की.

> विदेश सचिव ने भविष्य के रोडमैप में हितधारकों के रूप में भारत-श्रीलंका साझेदारी को मज़बूत करने में पड़ोसी पहले की नीति पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया. श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका की %बेहद उपयोगी% यात्रा के बाद हो रही है. उन्होंने कहा कि मोदी की इस यात्रा ने भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर दृष्टिकोण के अंतर्गत द्वीपीय राष्ट्र की महत्वपूर्ण स्थिति को और मज़बूत किया.

भारत का बांग्लादेश में रे संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव

नयी दिल्ली 16 जुलाई.भारत ने बंगलादेश के मैमनसिंह में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को गिराए जाने पर खेद व्यक्त करते हुए बंगलादेश सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और इस जगह को संग्रहालय बनाए जाने पर विचार करने को कहा है.

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोग देने को तैयार है.विदेश मंत्रालय ने मंगलवार देर रात एक वक्तव्य जारी कर कहा कि बंगलादेश के मैमनसिंह में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति, जो उनके दादा और प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी की थी को ध्वस्त किया जाना कष्टदायक है.वक्तव्य में कहा गया है कि यह संपत्ति अभी बंगलादेश सरकार के स्वामित्व में है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है. इमारत की ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए जो बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है, यह बेहतर होगा कि इसके विध्वंस पर पुनर्विचार किया जाए और साहित्य संग्रहालय तथा भारत और बंगलादेश की साझा संस्कृति के प्रतीक के रूप में इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के विकल्पों पर विचार किया जाए.